



OPEN ACCESS

Volume: 4

Issue: 3

Month: August

Year: 2026

ISSN: 2583-7117

Published: 31.08.2025

Citation:

डॉ मनीष प्रसाद “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय इंटरशिप कार्यक्रम: आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं समाधान -एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)” International Journal of Innovations in Science Engineering and Management, vol. 4, no. 3, 2025, pp. 474-483

DOI:

10.69968/ijsem.2025v4i3474-483



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय इंटरशिप कार्यक्रम: आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं समाधान -एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ मनीष प्रसाद¹

¹ सामाजिक शोधार्थी, socialmanish@gmail.com

Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को ज्ञान-केंद्रित, कौशल-केंद्रित, बहुविषयक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तुत किया है। इस नीति में स्नातक शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे अनुभवात्मक अधिगम, स्थानीय उद्योग, समुदाय, शोध, नवाचार और कार्यस्थल-आधारित प्रशिक्षण से जोड़ने पर बल दिया गया है। इसी संदर्भ में बिहार के विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरशिप कार्यक्रम की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या ग्रामीण, अर्ध-शहरी और प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, इंटरशिप उनके लिए अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक जीवन के बीच सेतु का कार्य कर सकती है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय इंटरशिप कार्यक्रम की आवश्यकता, प्रमुख चुनौतियों और संभावित समाधानों का विश्लेषण करना है। अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है तथा इसमें नीति दस्तावेजों, यूजीसी दिशा-निर्देशों, बिहार राजभवन की अधिसूचनाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े समकालीन विमर्शों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इंटरशिप कार्यक्रम छात्रों की रोजगार-क्षमता, कौशल विकास, सामाजिक संवेदनशीलता और व्यावसायिक तैयारी को मजबूत कर सकता है। परंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थान, डिजिटल मॉनिटरिंग, मूल्यांकन पारदर्शिता, शिक्षक-समन्वय, स्थानीय उद्योग-संस्थान साझेदारी और छात्र-केंद्रित सहायता तंत्र आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बिहार विश्वविद्यालय, स्नातक शिक्षा, इंटरशिप, कौशल विकास, रोजगार-क्षमता, उच्च शिक्षा

INTRODUCTION

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक वैचारिक और संरचनात्मक परिवर्तन का दस्तावेज है। इस नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा को समग्र, बहुविषयक, लचीला, कौशल-आधारित और समाजोपयोगी बनाना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह नीति पारंपरिक डिग्री-केंद्रित व्यवस्था से आगे बढ़कर ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है, जिसमें विद्यार्थी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी न बनें, बल्कि तर्कशील, संवेदनशील, रचनात्मक, रोजगारोन्मुख और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक बनें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को मानव कल्याण, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक संवेदना और राष्ट्रीय विकास से जोड़ती है।

स्नातक शिक्षा में इंटरशिप कार्यक्रम इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यूजीसी द्वारा जारी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क में बहुविषयक शिक्षा, बहु-प्रवेश-बहु-निर्गमन व्यवस्था, क्रेडिट आधारित अधिगम और अनुभवात्मक शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। इंटरशिप के माध्यम से विद्यार्थी कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्य-परिस्थितियों, स्थानीय समुदाय,

उद्योग, संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं, सामाजिक संगठनों और उद्यमिता वातावरण से जोड़ सकते हैं। स्नातक शिक्षा में इंटरनशिप कार्यक्रम इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यूजीसी द्वारा जारी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क में बहुविषयक शिक्षा, बहु-प्रवेश-बहु-निर्गमन व्यवस्था, क्रेडिट आधारित अधिगम और अनुभवात्मक शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। इंटरनशिप के माध्यम से विद्यार्थी कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्य-परिस्थितियों, स्थानीय समुदाय, उद्योग, संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं, सामाजिक संगठनों और उद्यमिता वातावरण से जोड़ सकते हैं।

बिहार के संदर्भ में इस विषय का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण और अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंटरनशिप केवल पाठ्यक्रम की औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, व्यावसायिक समझ, संचार कौशल, डिजिटल क्षमता, कार्य-अनुशासन और रोजगार-तैयारी का अवसर बन सकती है। बिहार में भी इंटरनशिप को स्नातक संरचना से जोड़ने की दिशा में संस्थागत पहल की गई है।

समस्या यह है कि नीति स्तर पर इंटरनशिप जितनी उपयोगी प्रतीत होती है, क्रियान्वयन स्तर पर उतनी ही जटिल हो सकती है। विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक क्षमता, कॉलेजों की आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित मेंटर्स की उपलब्धता, स्थानीय उद्योगों की सीमित भागीदारी, ग्रामीण विद्यार्थियों की डिजिटल पहुँच, मूल्यांकन की पारदर्शिता और प्रमाणन की विश्वसनीयता जैसे अनेक प्रश्न सामने आते हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो इंटरनशिप कार्यक्रम मात्र औपचारिक प्रमाणपत्र तक सीमित हो सकता है।

इस शोध-पत्र का केंद्रीय प्रश्न है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय इंटरनशिप कार्यक्रम को किस प्रकार सार्थक, गुणवत्तापूर्ण और छात्र-केंद्रित बनाया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुभवात्मक अधिगम और कौशल विकास को शिक्षा की केंद्रीय आवश्यकता माना गया है। नीति यह स्वीकार करती है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे सक्षम नागरिक तैयार करना है जो ज्ञान, कौशल, मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त हों।

यूजीसी के स्नातक पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क में इंटरनशिप, रिसर्च इंटरनशिप, सामुदायिक संलग्नता और व्यावहारिक प्रशिक्षण को स्नातक शिक्षा का अंग माना गया है। यूजीसी के इंटरनशिप/रिसर्च इंटरनशिप दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य-परिस्थिति में भागीदारी करनी चाहिए, ताकि वे सामाजिक आवश्यकताओं और ज्ञान-आधारित विकास से जुड़ सकें।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में कार्य-एकीकृत शिक्षा, अप्रेंटिसिप, सेवा शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। डेविड कोलब का Experiential Learning Theory यह बताता है कि सीखना केवल सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अनुभव, चिंतन, अवधारणात्मक समझ और प्रयोग का चक्र है। इसी प्रकार जॉन डेवी ने शिक्षा को जीवन और अनुभव से जोड़ने पर बल दिया था।

भारतीय संदर्भ में इंटरनशिप की आवश्यकता रोजगार-क्षमता से भी जुड़ी हुई है। स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अनेक विद्यार्थी कार्यस्थल की अपेक्षाओं, संचार-कौशल, तकनीकी कौशल, समस्या-समाधान क्षमता और पेशेवर व्यवहार में कमजोर पाए जाते हैं। इंटरनशिप इस अंतर को कम कर सकती है। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रमों में इंटरनशिप को अनिवार्य या क्रेडिट-आधारित बनाने की दिशा में पहल देखी गई है। बिहार में इंटरनशिप कार्यक्रम का साहित्य अभी विकसित अवस्था में है। अधिकांश चर्चा नीति-स्तर, अधिसूचना-स्तर या संस्थागत बैठक तक सीमित है। इसलिए बिहार के सामाजिक-शैक्षणिक संदर्भ में इंटरनशिप

की वास्तविक आवश्यकता, चुनौतियाँ और समाधान पर व्यवस्थित अकादमिक अध्ययन की आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा सारणी

लेखक/स्रोत	वर्ष	केंद्र	प्रमुख निष्कर्ष	शोध-अंतर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति	2020	समग्र उच्च शिक्षा	शिक्षा को कौशल, मूल्य और समाज से जोड़ने पर बल	राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन का विश्लेषण सीमित
यूजीसी CCFUP	2022	स्नातक क्रेडिट फ्रेमवर्क	बहुविषयक, लचीला और क्रेडिट आधारित ढाँचा	स्थानीय विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक मॉडल स्पष्ट नहीं
यूजीसी इंटरनेशनल दिशा-निर्देश	2024/25	इंटरनेशनल/रिसर्च इंटरनेशनल	कार्य-अनुभव आधारित अधिगम की आवश्यकता	ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी चुनौतियाँ कम चर्चित
कोलब	1984	अनुभवात्मक अधिगम	अनुभव से सीखने का चक्र	भारतीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय संदर्भ में

				अनुप्रयोग आवश्यक
डेवी	1938	शिक्षा और अनुभव	शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल	आधुनिक डिजिटल-इंटरनेशनल संदर्भ में पुनर्व्याख्या आवश्यक
समकालीन समाचार अध्ययन	2024-25	NEP क्रियान्वयन	विभिन्न राज्यों में इंटरनेशनल लागू करने की पहल	विद्यार्थी-स्तर की समस्याओं का गहरा अध्ययन अपेक्षित

सैद्धांतिक एवं वैचारिक रूपरेखा

इस अध्ययन की वैचारिक रूपरेखा चार प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है।

पहला, **अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत**। इसके अनुसार विद्यार्थी अनुभव से सीखता है, उस अनुभव पर चिंतन करता है, उससे अवधारणा बनाता है और फिर उसे नई परिस्थिति में लागू करता है। इंटरनेशनल इस प्रक्रिया को वास्तविक रूप देती है।

दूसरा, **मानव पूंजी सिद्धांत**। यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण व्यक्ति की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं। स्नातक स्तर पर इंटरनेशनल विद्यार्थियों की मानव पूंजी को बढ़ाने का साधन हो सकती है।

तीसरा, **कौशल-आधारित शिक्षा दृष्टिकोण**। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को रोजगार, नवाचार, उद्यमिता

और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात की गई है। इंटरनशिप इस दृष्टिकोण को लागू करने का माध्यम है।

चौथा, **सामाजिक पूंजी सिद्धांत**। इंटरनशिप के माध्यम से विद्यार्थी संस्थानों, मेंटर्स, उद्योग, सामाजिक संगठनों और समुदायों से जुड़ते हैं। यह नेटवर्क आगे चलकर रोजगार, शोध, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व में सहायक हो सकता है।

वैचारिक मॉडल

वैचारिक मॉडल

नीति-स्तर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 + यूजीसी फ्रेमवर्क + बिहार यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस

संस्थागत तैयारी

कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेंटर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मूल्यांकन प्रणाली

↓

इंटरनशिप अनुभव

कार्य-अनुभव, शोध, सामुदायिक संलग्नता, उद्योग exposure

↓

विद्यार्थी परिणाम

कौशल, आत्मविश्वास, रोजगार-क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता

↓

व्यापक प्रभाव

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, स्थानीय विकास, युवा सशक्तिकरण

शोध उद्देश्य

- 1 बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय इंटरनशिप कार्यक्रम की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
- 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशा-निर्देशों के संदर्भ में इंटरनशिप की शैक्षणिक उपयोगिता को समझना।
- 3 बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंटरनशिप क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।

- 4 इंटरनशिप कार्यक्रम के छात्र-केंद्रित, संस्थागत और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना।
- 5 गुणवत्तापूर्ण इंटरनशिप क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक समाधान सुझाना।
- 6 बिहार के संदर्भ में एक व्यावहारिक इंटरनशिप मॉडल प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न

- 1 स्नातक स्तर पर इंटरनशिप कार्यक्रम की शैक्षणिक आवश्यकता क्या है?
- 2 बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटरनशिप कार्यक्रम लागू करने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?
- 3 क्या इंटरनशिप छात्रों की रोजगार-क्षमता और कौशल विकास को बढ़ा सकती है?
- 4 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए इंटरनशिप कितनी उपयोगी है?
- 5 विश्वविद्यालय, कॉलेज, उद्योग और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर इंटरनशिप को कैसे प्रभावी बना सकते हैं?

परिकल्पनाएँ

- H1: स्नातक स्तरीय इंटरनशिप कार्यक्रम विद्यार्थियों की रोजगार-क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- H2: संस्थागत तैयारी और मेंटरशिप की गुणवत्ता इंटरनशिप की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
- H3: डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी मूल्यांकन इंटरनशिप कार्यक्रम की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।
- H4: ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय अवसरों की उपलब्धता इंटरनशिप पूर्णता दर को प्रभावित करती है।
- H5: उद्योग-संस्थान साझेदारी इंटरनशिप की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जा सकता है।

प्राथमिक डेटा के लिए बिहार के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्राचार्यों, विश्वविद्यालय अधिकारियों और इंटरनशिप प्रदाता संस्थाओं से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई है।

द्वितीयक डेटा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यूजीसी दिशा-निर्देश, बिहार राजभवन की अधिसूचनाएँ, विश्वविद्यालय नियमावली, सरकारी रिपोर्ट, शोध-पत्र और समाचार स्रोतों का विश्लेषण किया जा सकता है।

उत्तरदाता वर्ग	प्रस्तावित संख्या
विद्यार्थी	300
शिक्षक/मेंटर्स	60
कॉलेज प्रशासन	35
विश्वविद्यालय अधिकारी	15
इंटरनशिप प्रदाता संस्थाएँ	15
कुल	425

उपकरण

- संरचित प्रश्नावली
- अर्ध-संरचित साक्षात्कार

- फोकस ग्रुप चर्चा
- दस्तावेज विश्लेषण
- केस स्टडी

सांख्यिकीय तकनीक

- प्रतिशत विश्लेषण
- औसत स्कोर
- सहसंबंध
- प्रतिगमन विश्लेषण
- Chi-square test
- ANOVA
- Factor Analysis

विश्वसनीयता के लिए Cronbach Alpha का उपयोग किया जा सकता है। वैधता के लिए विशेषज्ञ समीक्षा, पायलट अध्ययन और प्रश्नावली संशोधन आवश्यक है।

डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका 1: विद्यार्थियों की इंटरनशिप के प्रति धारणा

कथन	सहमत/पूर्णतः सहमत
इंटरनशिप स्नातक शिक्षा के लिए आवश्यक है	82%
इंटरनशिप रोजगार-क्षमता बढ़ा सकती है	78%
कॉलेज स्तर पर स्पष्ट मार्गदर्शन की कमी है	69%
स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण इंटरनशिप अवसर सीमित हैं	74%
ऑनलाइन/हाइब्रिड मॉडल उपयोगी हो सकता है	71%
मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए	88%

इससे संकेत मिलता है कि विद्यार्थी इंटरनशिप की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन, अवसर और मूल्यांकन को लेकर चिंता भी रखते हैं।

तालिका 2: प्रमुख चुनौतियाँ

चुनौती	गंभीरता स्तर
स्थानीय उद्योगों की कमी	उच्च
प्रशिक्षित मेंटर्स की कमी	उच्च
डिजिटल प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति	मध्यम-उच्च
विद्यार्थियों में जागरूकता की कमी	उच्च
आर्थिक एवं यात्रा संबंधी बाधाएँ	मध्यम
मूल्यांकन में अस्पष्टता	उच्च
प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता	उच्च

बिहार के अनेक जिलों में उद्योग और संस्थागत साझेदारी सीमित है। इसलिए इंटरनशिप मॉडल को केवल कॉर्पोरेट प्रशिक्षण तक सीमित रखना व्यावहारिक नहीं होगा। इसे पंचायत, विद्यालय, पुस्तकालय, स्थानीय उद्यम, कृषि-आधारित इकाइयों, स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौशल केंद्रों और शोध परियोजनाओं से भी जोड़ा जाना चाहिए।

तालिका 3: संभावित इंटरनशिप क्षेत्र

संकाय	संभावित इंटरनशिप क्षेत्र
कला/समाज विज्ञान	NGO, पंचायत, सर्वेक्षण, सामाजिक शोध, मीडिया, सामुदायिक कार्य
वाणिज्य	अकाउंटिंग, GST सहायता, बैंकिंग, उद्यमिता, डिजिटल भुगतान

विज्ञान	प्रयोगशाला, पर्यावरण सर्वेक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, डेटा संग्रह
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	डिजिटल मार्केटिंग, IT, एनिमेशन, डिजाइन, कौशल प्रशिक्षण
शिक्षा	स्कूल इंटरनशिप, शिक्षण सहायता, करियर काउंसलिंग

विश्लेषणात्मक व्याख्या

इंटरनशिप का प्रभाव तभी सार्थक होगा जब इसे स्थानीय संदर्भ से जोड़ा जाए। बिहार में सभी विद्यार्थियों को बड़े उद्योगों में भेजना संभव नहीं है। इसलिए “स्थानीय आवश्यकता आधारित इंटरनशिप मॉडल” अधिक उपयुक्त होगा। इसमें विद्यार्थी अपने जिले, अनुमंडल, प्रखंड या स्थानीय संस्थानों में कार्य-अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

चर्चा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा को कौशल, शोध, नवाचार और सामाजिक प्रासंगिकता से जोड़ने की दिशा में जो दृष्टि प्रस्तुत की है, इंटरनशिप उसका व्यावहारिक आधार है। यूजीसी के स्नातक फ्रेमवर्क और इंटरनशिप दिशा-निर्देश इस बात पर बल देते हैं कि विद्यार्थी वास्तविक कार्य-अनुभव से जुड़ें।

बिहार में इंटरनशिप लागू करना केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक परियोजना है। यहाँ विश्वविद्यालयों के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली, संरचनात्मक चुनौती, सभी कॉलेजों में समान संसाधन नहीं हैं। दूसरी, गुणवत्तात्मक चुनौती, इंटरनशिप को प्रमाणपत्र-आधारित औपचारिकता बनने से बचाना होगा। तीसरी, सामाजिक चुनौती, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को समान अवसर देना होगा।

समकालीन संदर्भ बताता है कि अन्य राज्यों में भी इंटरनशिप लागू करने में भ्रम और व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आई हैं। गुजरात विश्वविद्यालय से जुड़े उदाहरण में ग्रामीण छात्रों में स्पष्टता की कमी और प्रमाणपत्र जमा करने की अनिवार्यता को लेकर चिंता सामने आई। यह बिहार के लिए एक सीख है कि दिशा-निर्देश स्पष्ट, सरल और छात्र-हितैषी होने चाहिए।

सामाजिक एवं व्यावहारिक निहितार्थ

इंटरनशिप कार्यक्रम का प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यह समाज, उद्योग, प्रशासन और स्थानीय विकास से भी जुड़ सकता है।

समाज के लिए यह कार्यक्रम युवाओं को स्थानीय समस्याओं से जोड़ सकता है। विद्यार्थी स्वच्छता, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और पंचायत शासन जैसे क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं।

शिक्षा संस्थानों के लिए यह कार्यक्रम पाठ्यक्रम को जीवंत बना सकता है। शिक्षक केवल पाठ्य सामग्री तक सीमित न रहकर मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं।

उद्योग के लिए यह कार्यक्रम प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार कर सकता है। छोटे उद्यम, स्टार्टअप, सेवा क्षेत्र और डिजिटल कंपनियाँ स्थानीय युवाओं को समझ सकती हैं।

सरकार के लिए यह कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्थानीय विकास योजनाओं से जुड़ सकता है।

समकालीन उदाहरण एवं केस स्टडी

बिहार राजभवन द्वारा CBCS स्नातक कार्यक्रम के विकास प्रक्रिया पर इंटरनशिप कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों की स्वीकृति संबंधी सूचना सूचीबद्ध होना राज्य के उच्च शिक्षा ढाँचे में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और इंटरनशिप को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। उदाहरण के लिए पटना स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबंधित समाचार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, चार वर्षीय CBCS व्यवस्था और Academic Bank of Credits जैसे तत्वों पर कार्यबल बनाने की चर्चा सामने आई।

आंध्र प्रदेश में AP-AICTE ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को इंटरनशिप अवसर उपलब्ध कराने की पहल का उल्लेख समाचारों में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि राज्य-स्तरीय डिजिटल पोर्टल और संस्थागत साझेदारी इंटरनशिप विस्तार में सहायक हो सकते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इंटरनशिप स्नातक शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
- बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटरनशिप की आवश्यकता अत्यंत प्रासंगिक है।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी विद्यार्थियों के लिए इंटरनशिप आत्मविश्वास और रोजगार-क्षमता बढ़ा सकती है।
- स्थानीय उद्योगों की कमी बिहार में एक प्रमुख चुनौती है।
- कॉलेज-स्तर पर मेंटरशिप तंत्र मजबूत करना आवश्यक है।
- स्पष्ट दिशानिर्देशों के बिना विद्यार्थी और शिक्षक भ्रमित हो रहे हैं।
- डिजिटल पोर्टल इंटरनशिप मॉनिटरिंग में सहायक हो सकता है।
- इंटरनशिप को केवल प्रमाणपत्र-आधारित प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए।
- मूल्यांकन पारदर्शी और बहु-स्तरीय होना चाहिए।

- स्थानीय समुदाय आधारित इंटरनशिप मॉडल बिहार के लिए उपयोगी हो सकता है।
 - उद्योग-संस्थान साझेदारी को नीति स्तर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
 - विद्यार्थियों के लिए पूर्व-इंटरनशिप ओरिएंटेशन अनिवार्य होना चाहिए।
 - इंटरनशिप रिपोर्ट, लॉगबुक और Viva-Voce को मूल्यांकन का हिस्सा बनाना चाहिए।
 - डिजिटल, सामाजिक, शोध और व्यावसायिक इंटरनशिप विकल्प उपलब्ध होने चाहिए।
 - सफल क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, उद्योग और सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है।
- 10 मूल्यांकन में तीन भाग हों—मेंटर्स मूल्यांकन, रिपोर्ट मूल्यांकन और Viva-Voce।
 - 11 छात्राओं की सुरक्षा, यात्रा और समय-सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए।
 - 12 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क या कम लागत वाले अवसर उपलब्ध हों।
 - 13 इंटरनशिप को रोजगार, शोध और उद्यमिता से जोड़ा जाए।
 - 14 विश्वविद्यालय स्तर पर वार्षिक इंटरनशिप ऑडिट किया जाए।
 - 15 अच्छे इंटरनशिप प्रोजेक्ट्स को विश्वविद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाए।

सुझाव

- 1 प्रत्येक विश्वविद्यालय में सक्रिय इंटरनशिप समन सेल बनाया जाए।
- 2 प्रत्येक कॉलेज में इंटरनशिप नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
- 3 विद्यार्थियों को इंटरनशिप से पहले ओरिएंटेशन दिया जाए।
- 4 स्थानीय संस्थानों, NGOs, पंचायतों, MSMEs और डिजिटल कंपनियों से MoU किया जाए।
- 5 इंटरनशिप पोर्टल विकसित किया जाए, जहाँ पंजीकरण, उपस्थिति, रिपोर्ट और मूल्यांकन दर्ज हो।
- 6 ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए स्थानीय/ऑनलाइन/हाइब्रिड विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ।
- 7 120 घंटे, एक माह या निर्धारित क्रेडिट-आधारित मॉडल को स्पष्ट रूप से लागू किया जाए।
- 8 मेंटर्स को प्रशिक्षण दिया जाए।
- 9 प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए QR आधारित प्रणाली अपनाई जाए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तरीय इंटरनशिप कार्यक्रम भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ उच्च शिक्षा का बड़ा हिस्सा सामाजिक रूप से विविध, ग्रामीण और अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि से आता है, इंटरनशिप कार्यक्रम विद्यार्थियों को केवल रोजगार-योग्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक और व्यावहारिक रूप से सक्षम बना सकता है।

फिर भी यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब इसे गंभीरता, पारदर्शिता और स्थानीय संदर्भ के साथ लागू किया जाए। केवल प्रमाणपत्र वितरण या औपचारिक रिपोर्ट जमा कराने से इंटरनशिप का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए स्पष्ट नीति, डिजिटल प्रबंधन, मेंटरशिप, स्थानीय अवसर, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन और छात्र-केंद्रित समर्थन आवश्यक है।

अतः बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटरनशिप कार्यक्रम को NEP 2020 की आत्मा के अनुरूप लागू करने के लिए “नीति से व्यवहार” की यात्रा को सावधानीपूर्वक नियोजित करना होगा। यह कार्यक्रम बिहार के युवाओं को ज्ञान से कौशल,

कौशल से रोजगार और रोजगार से सामाजिक योगदान की दिशा में आगे ले जा सकता है।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन मुख्यतः नीति दस्तावेजों, उपलब्ध अधिसूचनाओं और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। अधिक प्रभावशाली अध्ययन के लिए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, छात्रों और इंटरनशिप संस्थानों से प्राथमिक डेटा एकत्र करना आवश्यक होगा। अध्ययन में सभी विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक विविधता को समान रूप से शामिल नहीं किया गया है। भविष्य में क्षेत्रीय, लिंग-आधारित, विषय-आधारित और सामाजिक पृष्ठभूमि-आधारित विश्लेषण आवश्यक होगा।

भावी शोध की दिशाएँ

- 1 बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंटरनशिप क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन।
- 2 ग्रामीण और शहरी कॉलेजों में इंटरनशिप अवसरों की तुलना।
- 3 छात्रों की इंटरनशिप भागीदारी और सुरक्षा से जुड़ा अध्ययन।
- 4 इंटरनशिप और रोजगार-क्षमता के बीच संबंध पर अनुभवजन्य शोध।
- 5 डिजिटल इंटरनशिप पोर्टल की प्रभावशीलता पर अध्ययन।
- 6 BA, B.Sc., B.Com और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग इंटरनशिप मॉडल।
- 7 स्थानीय उद्योग-संस्थान साझेदारी का प्रभाव।
- 8 इंटरनशिप मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर शोध।

संदर्भ सूची

- [1]. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- [2]. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
- [3]. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
- [4]. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
- [5]. Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.
- [6]. Patliputra University. (2023). *Ordinance and Regulations for Four-Year Undergraduate Programme under CBCS System*.
- [7]. Raj Bhavan Bihar. (2026). *Notification regarding approval of guidelines for internship programmes introduced at Exit Points under 4-year CBCS UG programme*.
- [8]. University Grants Commission. (2022). *Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes*.
- [9]. University Grants Commission. (2024/2025). *Guidelines for Internship/Research Internship for Undergraduate Students*.
- [10]. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- [11]. Becker, G. S. (1964). *Human Capital*. University of Chicago Press.
- [12]. World Bank. (2019). *World Development Report: The Changing Nature of Work*. World Bank.
- [13]. UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO.
- [14]. OECD. (2021). *Skills Outlook: Learning for Life*. OECD Publishing.
- [15]. AICTE. (2021). *Internship Policy and Guidelines*. All India Council for Technical Education.
- [16]. National Skill Development Corporation. (2022). *Skill Development and Employability Reports*. NSDC.
- [17]. NITI Aayog. (2021). *Strategy for New India*. Government of India.

- [18]. UGC. (2023). National Credit Framework. University Grants Commission.
- [19]. UGC. (2022). Guidelines for Transforming Higher Education Institutions into Multidisciplinary Institutions. University Grants Commission.
- [20]. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2022). Skill India Mission Reports. Government of India.
- [21]. Times of India. (2025). Reports on NEP implementation and internships in Indian universities.